ग्रामीण ई–प्रशासन की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की चुनौतियाँ

प्रो0 स्वतन्त्र सिंह चौहान
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज,
शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी
एन.एच.–58, मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
(ए नैक एक्रेडीटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी)

ओमेन्द्र सिंह
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग
स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज,
शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी
एन.एच.–58, मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
(ए नैक एक्रेडीटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी)

सारांशिका

ई–प्रशासन आईसीटी द्वारा संचालित एक संगठन है जिसमें सरकार द्वारा अनेक प्रक्रियाऐं सम्पादित की जाती है। भारत में राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना मई 2006 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी जिसका उदद्श्ेय बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवा केन्द्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को जन सामान्य के लिए अपने स्थानीय स्तर पर सस्ती कीमत में सुलभ करना तथा इस तरह की सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। सरकार का तन्त्र देश का सबसे बड़ा और जन सामान्य से जुड़ा तन्त्र है और वहाँ प्रमाणित होने पर ही कोई भी बात स्वीकार्य होती है। परन्तु लघु स्तर पर हम उद्योग–धन्धे और स्वायत्त संस्थानों में बढ़ती ई–प्रशासन के परिणामों पर दृष्टि डालें तो परिणाम उत्साहवर्धक ही प्रतीत होंगें। कम्प्यूटर के प्रयोग करने पर आरम्भ में यह तर्क दिया जाता था कि जनसंख्या बाहुल्य भारत में कम्प्यूटर के प्रयोग से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु यह तर्क कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग को रोक नहीं पाया है। उसी तरह ई–प्रशासन के विरूद्व भी यह तर्क दिया जा सकता है कि रोजगार भी घटेगा। तर्क यह भी है कि गुणात्मक विकास के मार्ग में परिमाणात्मक विकास की कमी का तर्क भी अवरोध खड़ा करता है। मगर गुणात्मक विकास की अभिव्यक्ति को भटकाया जा सकता है, परन्तु नकारा नहीं जा सकता है। वर्तमान में ई–प्रशासन भारत के आर्थिक–राजनैतिक तन्त्र के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की अनिवार्यता सामने आई है। तकनीकी विकास ने जहाँ एक ओर संम्पूर्ण विश्व को वैश्विक गाँव (Global Village) का रूप दिया है वही शासन की शैली भी परिवर्तित हुई है। ऐसे में शासन ई–प्रशासन को जनता के लिए अनुकूल, पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाता है और प्रत्येक स्तर पर जनता और प्रशासन के बीच आने वाली समस्याओं का निवारण करने की दिशा में एक श्रेष्ठ विकल्प भी है। धरातलीय स्तर पर ग्राम ही प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी है। ई–प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण जन न केवल नियम कानून एवं कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपितु संरचनात्मक–कार्यात्मक सुधारों हेतु विधिवत तरीके से योगदान भी दे सकते हैं। ई–शासन द्वारा ग्रामीणों में सुशासन स्थापित किया जाता है। अतः ग्रामीण ई–प्रशासन प्रणाली एवं नागरिकों के मध्य सामजंस्य स्थापित करने हेतु ई–प्रशासन नीति की उपलब्ध सुविधाओं, योजनाओं को जानने एवं उनसे लाभ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विषय का चयन किया है। क्योंकि बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण स्थानीय स्तर पर जागरूकता का होना भी आवश्यक है। **''एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए''**।

मुख्य शब्द : ई–प्रशासन, भविष्य, चुनौतियाँ, ग्रामीण–स्थिति, वर्तमान, चरण।

प्रस्तावना

ई–प्रशासन से तात्पर्य सरकारी कामकाज में संचार एवं सूचना तकनीकी का प्रयोग करना है, जिससे शासन सरल, नैतिक, उत्तरदायी और जवाबदेही बन सके। इसके माध्यम से सरकार और आम जनता के बीच इंटरनेट या कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सुरक्षित, विश्वसनीय और नियन्त्रित संपर्क कायम करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान ही एक अवसर है – श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। निसंदेह ई–प्रशासन से गांवों के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब गाँव का व्यक्ति घर बैठे देश–विदेश की सेवाओं का लाभ ले रहा है जिसमें रेल में आरक्षण एवं टिकट, परीक्षा का फार्म भरना, परिणाम जानना, टैक्स जमा करना, चिकित्सालय में नम्बर लेना, प्रमाण–पत्र बनवाना, सब ई–प्रशासन से आसान हो गया है। लेकिन अभी भी भारत में ई–प्रशासन को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है जिसमें काफी चुनौतियों से भी रूबरू होना पड़ेगा। भारत में ई–प्रशासन की वास्तविक शुरूआत 1976 से मानी जाती है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) एवं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नामक परियोजना ही विस्तारित होकर वर्ल्ड वाइड वेब (www) का जन्म ले चुकी हैं। वर्तमान युग में सूचना आर्थिक विकास की कुंजी है। इसलिए पूरी व्यवस्था सूचना के चारों ओर घूम रही है। इसका उदद्श्ेय लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है। इस कार्यान्वयन हेतु कुछ तात्कालिक और प्रांसगिक चुनौतियां है। जैसे साइबर अपराध, भाषा, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, अधिगम रूप में परिलक्षित होती हैं।

ई–प्रशासन के चरण : नागरिक व्यवस्था का व्यापक प्रसार करने हेतु इलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग करना ही ई–प्रशासन है। साथ ही किसी भी संगठन, समाज या व्यवस्था के विविध आयामों को नियन्त्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने की श्रृंखला में सूचना तकनीकी का प्रयोग करना ही ई–प्रशासन है। यद्यपि सूचना क्रांति का भारत के ग्रामीण निर्धनों पर भी प्रभाव पड़ा है। सरकार ने नवीन सूचना तकनीकी के लाभों को निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली 40ः से अधिक जनसंख्या तक पहुँचाने का लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु कार्य काफी कम है। ई–प्रशासन की कुछ श्रेणियाँ हैं जैसे–

जी0टू0जी (सरकार से सरकार तक), जी0टू0सी0 (सरकार से जनता तक), जी0टू0बी0 (सरकार से व्यवसाय तक), जी0टू0ई0

(सरकार से कर्मचारी तक),

सी0टू0सी0 (नागरिक से नागरिक तक)

ये श्रेणियां प्रशासन के उपसर्ग–ई–दक्षता, सशक्तिकरण एवं प्रभावशीलता के साथ ऑनलाईन काम कर रहा है। इससे खर्चे के साथ ही समय की बचत तो होती है साथ ही काम करना भी सरल हो गया है। लेकिन ग्रामीण ई–प्रशासन की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करना भी आवश्यक है। आम आदमी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतू तर्क संगत मूल्यों पर ई–सेवाओं की कुशलता, पारदर्शिता, विश्वसनीय सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

ग्रामीण ई–प्रशासन की वर्तमान स्थिति : विश्व के समक्ष कई साझे संकट और चुनौतियाँ है जिनमें स्वच्छता, धर्मनिष्ठा, शिक्षा, कौशल विकास, व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि, विज्ञान और तकनीकी विकास आदि विषय समाहित हैं। भारत गाँवों का कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। ये निश्चित ही जनसंख्या का बाहुल्य भी गाँवों में निवास करता है ऐसे में ग्रामीण ई–प्रशासन की राह एवं उपलब्धियाँ वैश्विक दृष्टिकोण पर अवलम्बित होनी चाहिए। जिसके लिए ग्रामीण ई–प्रशासन की वर्तमान स्थिति पर विचार मंथन लेखबद्व होना चाहिए। जिससे हम अपने अतीत के अनुभवों का लाभ वर्तमान को सवारने में उपयोग करें, और भविष्य की चुनौतियों को स्वर्णिम अवसरों में परिवर्तित कर सकें।

हम अपने चहुँ ओर देख रहे हैं कि सूचना अब (Social Media) आर्थिक विकास की कुंजी है। इसीलिए गाँवों से नगरों तक पूरी व्यवस्था वैश्विक पटल पर सूचना जन माध्यमों के चहुँ ओर घूम रही है। वास्तव में ई–प्रशासन एक विस्तृत अवधारणा है जो केवल प्रशासनीय व्यवस्था से ही नहीं अपितु इसमें राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा अन्य आयामों से भी सम्बन्धित है।

आज कोविड–19 के विभिन्न रूपों के उपरान्त देखा जा रहा है कि भारत के गाँवों में ई–प्रशासन को सशक्त बनाने की भूमिका में ई–प्रशासन के प्रयास में सूचना तकनीकी ने एक शक्तिशाली औजार की भूमिका का कार्य किया है। जिसमें ई–प्रशासन, ई–शिक्षा, ई–व्यापार, ई–वाणिज्य, ई–चिकित्सा आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ ई–प्रशासन ने पारदर्शिता के साथ त्वरित एवं क्रांतिकारी सुव्यवस्था का परिचय दिया है। आज ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश–विदेश की घटनाओं से भली–भाँति परिचित हो रहें हैं। विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी एक आमजन तक इन्टरनेट के द्वारा प्रेषित की जा सकती है जिससे कि सबका साथ सबका विकास उदद्श्ेय की पूर्ति हो रही है। जैसे कि–

ज्ञान आधारित भारत के निर्माण में ई–प्रशासन एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसकी दिशा में सरकार ने 27 दिसम्बर 2011 को लोकसभा में इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011 पेश किया।

एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए अर्थात् विस्तृत दृष्टिकोण में किसी भी संगठन समाज या व्यवस्था के विविध पक्षों को नियन्त्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना तकनीक का प्रयोग करना ई–प्रशासन है। भारत के इतिहास में ज्ञात होता है कि मानव सभ्यता को क्रांतियाँ प्रभावित करती आई हैं। जैसे– कृषि क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक विकास को गति प्रदान की। दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति ने मानव को भौतिकवादी तथा आधुनिक जीवन का वरदान दिया। तीसरी क्रांति के रूप में सूचना तकनीकी क्रांति ने व्यक्ति को वैश्विक रूप प्रदान किया। सूचना क्रांति का भारत के ग्रामीण निर्धनों पर काफी कम प्रभाव पड़ा है। जबकि सरकार द्वारा सूचना तकनीकी को जनसाधारण तक पहुँचाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृति प्रदान कर रही है क्योंकि सु–शासन केवल सूचना और संचार तकनीकी के प्रभाव तक ही सीमित नहीं है अपितु सभी जन नागरिकों को भी इस तकनीकी का लाभ प्राप्त हो, एवं वह अवसरों की पहुँच में भी सक्षम वाहक होना चाहिए। ई–प्रशासन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है– सरकार के निर्णयों में सुधार करना एवं लोगों के विश्वास में वृद्वि करना। सरकार की जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाना तथा सुव्यवस्था रखना, नई चुनौतियों का सामना करने हेतु संगठनों, व्यवसायियों एवं इच्छुक व्यक्तियों को सम्मिलित करना। इस प्रकार ई–प्रशासन बहुत ही तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण है। शासन के महत्वपूर्ण पहलु हैं– पारदर्शिता, भागीदारी, प्रतिभागिता, अनुक्रियाशीलता, दायित्वशीलता, प्रभावशीलता, समता एवं समावेशन, जवाब देयता, मतैक्यता, विधि का शासन, वैधता, परिवर्तन। वर्तमान में ई–प्रशासन में कुछ संभावनाएं प्रदर्शित हो रही हैं जैसे– ये इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान करता है तथा विकास एवं प्रयोग को विश्वसनीयता के साथ प्रोत्साहित भी करता है। ई–प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान होता है। मगर सभी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तथा शैक्षणिक पिछड़ापन व जागरूकता में कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के प्रयोग के प्रति रूझान की भी कमी है। जबकि इसकी जीवन में बहुत उपयोगिता है जैसे–

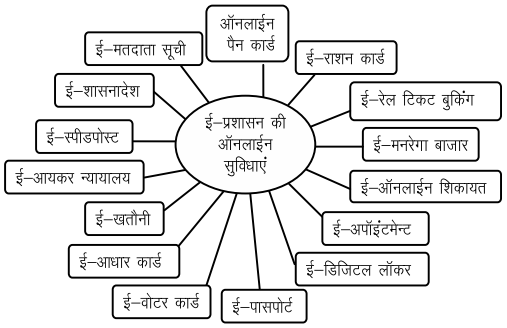

ग्रामीण ई–प्रशासन एवं साइबर अपराध के रूप में भविष्य की चुनौतियाँ : परम्परागत प्रक्रिया लीक से हटकर ई–प्रशासन सरकार और जनसाधारण के मध्य संवाद स्थापित करने हेतु सशक्त सेतुबन्ध है जिससे कार्य करना सरल तो हुआ ही है साथ ही देश के कोने–कोने तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ऐसे ही ई–प्रशासन की वर्तमान दशा में सूचना तकनीकी के दुरूपयोग के कारण साइबर अपराधों के बढ़ने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। साइबर अपराध एवं इन्टरनेट के दुरूपयोग की गति को भौगोलिक परिधि में बाँधा नहीं जा सकता है। जल, थल और नीलाम्बर तीनों ही क्षेत्रों में साइबर अपराध की निरन्तर वृद्वि हो रही है। आजकल हम अपने चारों ओर देख एवं सुन रहे हैं कि ई–प्रशासन का मतलब स्मार्ट गवर्नमेन्ट से है– स्मार्ट– SMART – S-Simple, M-Model, A-Accountability, R-Responsibility & T-Transpiercy अर्थात् ई–प्रशासन (E-Governance) या इलैक्ट्रोनिक प्रशासन। लेकिन शासन कोई भी सुरक्षा संबंधी कानून बनाती है तो अपराधी पहले ही उसका तोड़ भी ढूँढ निकाल लाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि

''सौ राजा की बुद्वि एक चोर में होती है'' या ''चोर ही चाँदनी रात न भावा'' अर्थात् अपराधियों की बुद्वि अंधेरे में ही काम करती है। जो अपराधिक कार्य संचार माध्यमों से जुड़े हैं साइबर अपराध कहते हैं। जैसे–बैंक में हेरा–फेरी, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, हैकिंग, अश्लील संदेश, मोबाइल का दुरूपयोग, विपरीत कार्य, गुप्त सूचनाओं की चोरी आदि क्रियाओं की साइबर अपराध की श्रेणी में बांधा जा सकता है।

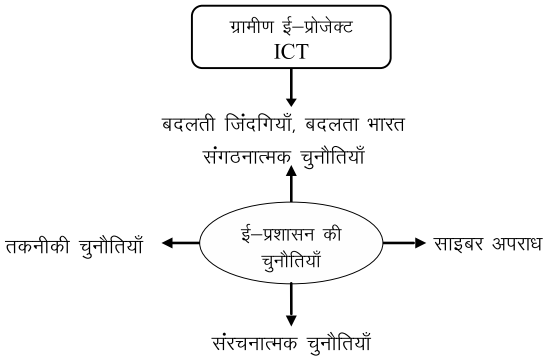

- माईगोव – शासन में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन
- डिजिटल सेवा – डिजिटल फासलों को पाटने का कदम
- भारत को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल एक प्रगति के पथ पर
- आधार–विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन पहचान का प्लेटफार्म
- डिजिलॉकर द्वारा शासन की ओर बढ़ते कदम
- इलैक्ट्रोनिक्स निर्माण नयी ऊँचाई के शिखर पर
- जीवन प्रमाण–पेंशनभोगियों के लिए वरदान
- ई–क्रांति–सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी
- आई टी, आई टी ई एस सेक्टर के विकास को बढ़ावा।

दैनिक जीवन में हर कोई न कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो रहा है। जैसे फिशिंग पायरेसी, पहचान की चोरी, मैलवेयर अटैक, एटीएम धोखा, साइबर शोषण, पोनोग्राफी, पेटेन्ट प्रोडक्ट की चोरी, बदले की भावना, लालच, धोखा देना आदि है। निसंदेह ई–प्रशासन के लाभ एवं उपयोगिता के साथ ही साइबर अपराधों की बढ़ती समस्या एक चुनौती है जिसका हल तलाशना अनिवार्य है।

अतः इस चुनौती का सामना करने हेतु ई–अदालत, प्रशिक्षित पुलिस, प्रशिक्षित वकील, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। साइबर अपराध एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग ईन्टरनेट या कम्प्यूटर के माध्यम से गलत काम या अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए किया जाता है। दिन प्रतिदिन यह हमारे समाज के लिए खतरा बनते जा रहें हैं क्योंकि हैकरों द्वारा कई लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। व्यक्ति के घर पर पैसे की हानि, संगठन के स्तर पर गोपनीय डेटा चोरी लीक हो चुकें हैं। ऐसे भयावह कार्यो से सुरक्षित रहने हेतु सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर गोपनीयता सेटिंग्स को बनाए रखें। आज प्रत्येक व्यक्ति निर्भय रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं और हजारों लोगों तक पहुँच सकते हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी। अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा तभी हम ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बच सकते हैं क्योंकि लगभग हर चौथे साइबर अपराध में मोबाइल का प्रयोग होता है।

निष्कर्ष : ग्रामीण ई–प्रशासन के परिणामस्वरूप गाँव अब पहले जैसे नहीं है। नित नूतन परिवर्तन को अंगीकृत करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है। डिजिटलीकरण के कारण ग्रामीण व्यक्ति भी बुद्वि एवं कौशल के बल पर ग्रामीण एवं शहरी दूरी को पाटता जा रहा है। ग्रामीण अंचल में ही वह अपने स्वर्णिम भविष्य की तस्वीर में इन्द्रधनुषी रंग उकेरने की कोशिश कर रहा है। समग्र रूप में देखें तो ई–प्रशासन के द्वारा अब ग्रामीण रहन–सहन का तरीका, वेशभूषा, खानपान, आय के साधन और ग्रामीण परिवेशीय संरचना सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। हुनर आधारित सोच विकसित हो रही है। वहीं वर्तमान सरकार कुछ सरकारी योजनाओं द्वारा इनकी आत्मनिर्भरता में वृद्वि के प्रयास हेतु तत्पर है। जैसे– मनरेगा, उज्जवला, शौचालय, मकान, राशन, जन–धन योजना, पेंशन एवं स्वास्थ्य (आयुष), मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील, छात्रवृत्ति, नौकरियों में आरक्षण इत्यादि ग्रामीण स्तर को ऊँचे पायदान पर ला रहें हैं। इंटरनेट सुविधाओं ने तो मानो ग्रामीणों व्यक्ति के आत्मविश्वास को चार चाँद लगा रखे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को सशक्त किया जा रहा है। अब ई–प्रशासन के कार्यान्वयन में विशेषकर सभी चरणों पर प्रयोग सम्बन्धी चुनौतियों पर ध्यान देने का समय आ गया है, जिससे शासन में अधिक व्यापक परिवर्तन लाए जा सकते है जिसके लिए इंटरनेट पर अन्योन्याश्रितता प्लेटफार्म की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी तथा स्थानीय भाषाओं में संचार में वृद्वि करनी होगी। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाये एवं सूचना की उपयोगिता से अवगत कराया जाये। क्योंकि सूचना एवं संचार तकनीकी लोगों को प्रभावी ढंग से सेवा वितरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

सन्दर्भ सूची :

1. Annual Report-(2004-2005) Department of Information Technology, Govt. of India.
2. Devaiah. N.G Keertiraj (2021) E-Governance In India Challenges and Strategies.
3. Dubey, M (2003) Less Paper Governance, Paper Presenited at EROPA conference, New Delhi.
4. Mathias Finger (2012) E-Governance A Global Journey
5. Narayan Singh (2017) One Yhought on "E-Governance".
6. Pradeep Suri (2017) Introduction to E-Governance.
7. Sandeep Bhandari (2021) MPA0/7, E-Governance (IGNOU) help book.
   - Internet
   - Newspapers, Journals and Social Media Platform.
   - Hi.vikaspedia.in>e-governance
   - Hi.m.wikipedia.org>wiki> bZ&iz'kklu
   - www.digitalindia.gov.in
   - www.egyankosh.ac.in>bitstream>unit1
   - www.drishtias.com,e-governance-S
   - www.mpgkpote.com